लाभ के लिए किसी योजना के लागू करने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें आत्म-निर्भर बनाया जा सके और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुलापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1990-91 के दौरान देश में कुल मत्स्य उत्पादन 38.36 लाख मीटरी टन हुआ और तदनुरूपी अवधि के दौरान निर्यात किया गया समुद्री उत्पाद 1.38 लाख मीटरी टन था

(ग) और (घ) समुद्री मछुआरों के लाभ के लिए सरकार द्वारा फिलहाल क्रियान्वयनाधीन तथा 1991-92 वर्ष के लिए क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण उत्पादनोन्मुखी योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण।

(2) मत्स्य ग्रहण जलयान, जिनकी लम्बाई 20 मीटर से कम हो, द्वारा प्रयुक्त उच्च गति डिजिल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(3) नान ट्रालर प्रकार की एफ. आर.पी. मत्स्य ग्रहण नौकाओं, जिनकी लम्बाई 12-15 मीटर हो, को चलाकर अपतटीय पेलैजिक मात्स्यिकी संसाधनों का उपयोग करना।

(4) डोंगा तथा कैटामारान के बदले में प्लाईवूड मत्स्य ग्रहण नौकाओं को चलाना।

(5) जलीय प्रदेश में समुद्री मत्स्यग्रहण विनियमन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पैट्रोल चालित नौका प्राप्त करने के लिए समुद्रवर्ती राज्य सरकारों का वित्तपोषण करना।

इस्पात और लोहे के मूल्यों में वृद्धि

492. श्री राम जेठमलानी
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये का हाल ही में किए गए अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश में इस्पात और लोहे के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मूल्य-वृद्धि 400 रुपये से 500 रुपये प्रति टन तक हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और ये कदम मूल्य-वृद्धि को रोकने में कहां तक प्रभावी रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा प्रशासित लोहे और इस्पात के मूल्यों में अभी हाल में कोई वृद्धि नहीं की गई। कुछ क्षेत्रों में लोहे और इस्पात की कुछ मदों के खुले बाजार मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु यह पूर्णतया अवमूल्यन के कारण ही नहीं कहा जा सकता।

देश में इस्पात का उत्पादन

493. श्री राम जेठमलानी
सरदार बूटा सिंह अरोड़ा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल 1991 के फाइनेंशियल एक्सप्रैस में "आउटपुट टू बी 5 लाख टन्स शार्ट आफ टारगेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो फरोस इकाइयों द्वारा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इकाइयों को समय-समय पर उचित मूल्य पर स्क्रैप उपलब्ध नहीं कराया जाता है और क्या यह भी सच है कि देश में इस वर्ष स्क्रैप का कम मात्रा में आयात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन इकाइयों को युक्तिसंगत दरों पर स्क्रैप की पर्याप्त मात्रा में नियमित पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कोई योजना कार्यान्वित करेगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है जो गौण इस्पात क्षेत्र द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान उत्पादित किया जाना हो । तथापि, इस वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक नहीं था ।

(ग) स्वदेशी रूप से उत्पादित स्क्रैप का मूल्य बाजार के दबावों द्वारा तय किया जाता है । आयातित स्क्रैप को मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एम.एस.टी.सी.) जो स्वीकृत नियमों/कार्यपद्धतियों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर पोत लदान को निबन्धित करता है, द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं को समान आधार पर सप्लाई किया जाता है । वास्तविक प्रयोक्ता आर.ई.पी. लाइसेंस के माध्यम से भी स्क्रैप का आयात कर सकते हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान एम.एस.टी.सी. ने विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय अड़चनों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कम मात्रा में स्क्रैप का आयात किया ।

(घ) उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में स्क्रैप की नियमित सप्लाई तभी संभव हो सकती है जब पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो ।

Ownership rights under Apartment ownership Act

494. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether D.D.A. have taken a decision to confer ownership rights on allottees under the Apartment Ownership Act; and

(b) if so, the details of the decision taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Modalities of the implementation of the Apartment Ownership Act are being worked out.

Modernisation of Allahabad railway station

495. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether Government have formulated any plans to further modernise Allahabad railway station in view of its importance as a big pilgrim centre?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): Yes, Sir. Work of provision of a 125 bedded Rail Yatri Niwas has been sanctioned recently at an estimated cost of Rs. 3.93 crore. Works pertaining to lengthening of existing platforms, provision of new platforms, extension to foot over bridges and certain improvements to circulating areas have also been completed recently. Further works of provision of additional platforms and extension to existing platforms are also in hand at present.

Unauthorised steel production by induction furnaces and re-rollers

496. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that around 20 per cent steel produced in the secondary sector is carried out by unauthorised in-